VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 28.5.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

INDIAN ECONOMY 1950–1990

Question 7:

What is Green Revolution? Why was it implemented and how did it benefit the farmers? Explain in brief.

ANSWER:

Due to low productivity, frequent occurrence of famines and low levels of agricultural products in the latter half of second five year plan, a team was formed to suggest various ways to counter these problems. As per the recommendations of the team, government introduced the use of HYV seeds, modern techniques and inputs like fertilisers, irrigation facilities and subsidised credit. These steps collectively are known as Intensive Area Development Programme (IADP). Consequently, in the year 1967-68, food grains production increased nearly by 25%. Due to this substantial increase of food grains production, this outcome is known as 'Green Revolution'. The word Green Revolution comprises of two words 'Green' that is associated to crops and 'Revolution' is associated to the substantial increase. कम उत्पादकता, अकाल की लगातार घटनाओं और कृषि उत्पादों के निम्न स्तर के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में, इन समस्याओं का सामना करने के विभिन्न तरीकों का सुझाव देने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने HYV बीजों, आधुनिक तकनीकों और उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और रियायती ऋण जैसे आदानों का उपयोग शुरू किया। इन चरणों को सामूहिक रूप से गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (IADP) के रूप में जाना जाता है। नतीजतन, वर्ष 1967-68 में, खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन की इस पर्याप्त वृद्धि के कारण, इस परिणाम को 'हरित क्रांति' के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द में दो शब्द शामिल हैं Green ग्रीन 'जो फसलों से संबंधित है और' क्रांति 'पर्याप्त वृद्धि से जुड़ा है।

Need of Green Revolution

The needs of Green Revolution are as follows.

1. Low Irrigation Facility: The well irrigated and permanent irrigated area was only 17% in 1951. The major part of area was dependent on rainfall and, consequently, agriculture suffered from low level of production. कम सिंचाई सुविधा: अच्छी तरह से सिंचित और स्थायी सिंचित क्षेत्र 1951 में केवल 17% था। इस क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा वर्षा पर निर्भर था और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन के निम्न स्तर से पीड़ित थी।

2. Conventional and Traditional Approach: The use of conventional inputs and absence of modern techniques further hampered the agricultural productivity. पारंपरिक और पारंपरिक दृष्टिकोण: पारंपरिक आदानों के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के अभाव ने कृषि उत्पादकता में और बाधा उत्पन्न की।

3. Frequent Occurrence of Famines: Famines in India were very frequent during the period 1940s to 1970s. Further, due to higher growth rate of populations, agriculture failed to grow at the same speed. परिवारों की बारंबारता: 1940 से 1970 के दशक के दौरान भारत में परिवार बहुत अधिक थे। आगे, आबादी की उच्च विकास दर के कारण, कृषि उसी गति से बढ़ने में विफल रही।

4. Lack of Finance (credit): Small and marginal farmers found it very difficult to get finance and credit at cheap rate from the government and banks ,hence, fell an easy prey to the money lenders. वित्त की कमी (क्रेडिट): छोटे और सीमांत किसानों को सरकार और बैंकों से सस्ते दर पर वित्त और ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन लगा, इसलिए, धन उधारदाताओं के लिए एक आसान शिकार बन गया।

5. Self-sufficiency: Due to the traditional agricultural practices, low productivity, and to feed growing population, often food grains were imported that drained away scarce foreign reserves. It was thought that with the increased production due to Green Revolution, government can maintain buffer stock and India can achieve self-sufficiency and self-reliable. आत्मनिर्भरता: पारंपरिक कृषि पद्धतियों के कारण, कम उत्पादकता, और बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए, अक्सर खाद्यान्न का आयात किया जाता था जो दुर्लभ विदेशी भंडार को खत्म कर देता था। यह सोचा गया था कि हरित क्रांति के कारण बढ़े हुए उत्पादन के साथ, सरकार बफर स्टॉक बनाए रख सकती है और भारत आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वसनीय हासिल कर सकता है।

6. Marketising Agriculture: Agriculture was basically for subsistence and, therefore, less amount of agricultural product was offered for sale in the market. Hence, the need was felt to encourage the farmers to increase their production and offer a greater portion of their products for sale in

the market. विपणन कृषि: कृषि मूल रूप से निर्वाह के लिए थी और इसलिए, बाजार में बिक्री के लिए कृषि उत्पाद की कम मात्रा की पेशकश की गई थी। इसलिए, किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने और बाजार में बिक्री के लिए अपने उत्पादों के एक बड़े हिस्से की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

Question 8:

Explain 'growth with equity' as a planning objective.

ANSWER:

Both growth and equity are the two important aspects of India's five year plans. While growth refers to the increase in GDP over a long period of time equity refers to an equitable distribution of GDP so that the benefits due to higher economic growth are shared by all sections of population. Equity implies social justice. Growth itself is desirable but growth in itself does not guarantee the welfare of people. Growth is assessed by the market value of goods and services (GDP) and it may be possible that the goods and services that are produced may not benefit the majority of population. In other words, only a few with high level of living and money income may get the share of GDP. Hence, growth with equity is a rational and desirable objective of planning. This objective ensures that the benefits of high growth are shared by all the people equally and, hence, this not only leads to reduction of inequality of income, poverty promotion of egalitarian society but also enables everyone to be self-reliant. Therefore, to conclude, it can be said that growth with equity is the most important objective of an economic planning. विकास और इक्विटी दोनों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जबकि विकास जीडीपी में वृद्धि को संदर्भित करता है समय की लंबी अवधि के लिए इक्विटी जीडीपी के समान वितरण को संदर्भित करता है ताकि उच्च आर्थिक विकास के कारण लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा साझा किए जाएं। समानता का तात्पर्य सामाजिक न्याय से है। विकास स्वयं वांछनीय है लेकिन अपने आप में विकास लोगों के कल्याण की गारंटी नहीं देता है। विकास का मूल्यांकन वस्तुओं और सेवाओं (जीडीपी) के बाजार मूल्य से किया जाता है और यह संभव हो सकता है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनमें से अधिकांश आबादी को लाभ न हो। दूसरे शब्दों में, उच्च स्तर के जीवित और धन आय वाले कुछ ही जीडीपी का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, इक्विटी के साथ विकास योजना का एक तर्कसंगत और वांछनीय उद्देश्य

है। यह उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि उच्च विकास का लाभ सभी लोगों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है और इसलिए, यह न केवल आय की असमानता को कम करता है, बल्कि समतावादी समाज की गरीबी को बढ़ावा देता है, बल्कि सभी को आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाता है। इसलिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि इक्विटी के साथ विकास एक आर्थिक नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है।